

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3375  
20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

**इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती**

**†3375. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि सहित तैनात की गई ई-बसों की कुल संख्या और उक्त ई-बसों की परिचालन स्थिति संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-बस की तैनाती के बाद राज्य-वार वर्तमान में संचालित और चरणबद्ध तरीके से हटाई गई आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) बसों, दोनों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में जोड़ी गई ई-बसों की संख्या सहित उनकी परिचालन स्थिति का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएमई-बस सेवा योजना के तहत ग्यारह शहरों में 650 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए आंध्र प्रदेश पात्र है;

(ङ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में तैनात बसों का ब्यौरा क्या है और साथ ही आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) आंध्र प्रदेश को बिहाइंड-द-मीटर पावर और सिविल डिपो अवसंरचना के लिए कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है, तथा इसके उपयोग की स्थिति क्या है?

**उत्तर**  
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**  
**(श्री तोखन साहू)**

(क) और (ख) इस मंत्रालय की डेटा प्रबंधन प्रणाली इस तरह की मांगी गई जानकारी नहीं रखती। हालाँकि, इस मंत्रालय ने 16 अगस्त 2023 को केंद्र प्रायोजित के रूप में “पीएम-ई-बस

सेवा योजना" शुरू की है, जिसका उद्देश्य पीपीपी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) से शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ाना है। अब तक मंत्रालय ने 14 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 7,293 ई-बसों को स्वीकृति दी है (राज्य-वार स्वीकृत बसों की जानकारी अनुलग्नक-1 में दी गई है)।

- (ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 9 मीटर वाली कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें फ़ास्टर अडाप्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (एफएएमई) इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2021-22, 2022-23 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) के तिरुपति जिले के अलीपीरी डिपो में लगाई गई थी। इन 100 ई-बसों में से, 50 ई-बसें तिरुपति-तिरुमाला घाट रूट पर और शेष 50 ई-बसें इंटरसिटी रूट (कडप्पा-तिरुपति, मदनपल्ली-तिरुपति, नेल्लोर-तिरुपति) पर चल रही हैं।
- (घ) पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य 11 शहरों में 750 ई-बसें चलाने के लिए पात्र है। शहर-वार विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।
- (ङ) और (च) पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को कुल 750 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं। एपीएसआरटीसी सफल बोलीदाता (ऑपरेटर) को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के चरण में है। बिहाइन्ड-द-मीटर पावर और सिविल डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

\*\*\*\*

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत राज्यवार स्वीकृत ई-बसें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत बसों की संख्या
असम	100
आंध्र प्रदेश	750
बिहार	400
छत्तीसगढ़	240
गुजरात	450
हरियाणा	450
कर्नाटक	750
मध्य प्रदेश	582
महाराष्ट्र	1559
मेघालय	50
ओडिशा	400
पंजाब	347
राजस्थान	675
उत्तराखंड	150
चंडीगढ़	100
जम्मू और कश्मीर	200
लद्दाख	15
पुदुचेरी	75
<b>कुल</b>	<b>7293</b>

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को स्वीकृत ई-बसों का विवरण

क्र. सं.	शहर	स्वीकृत ई-बस
1	विशाखापत्तनम	100
2	विजयवाड़ा	100
3	गुंटूर	100
4	नेल्लोर	100
5	कुरनूल	50
6	काकीनाडा	50
7	राजमुंदरी	50
8	कडपा	50
9	अमरावती	50
10	तिरुपति	50
11	अनंतपुर	50
कुल		750

\*\*\*\*\*